भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 5448
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना

5448. सुश्री सयानी घोषः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं के लिए एक नई पीएलआई योजना शुरू करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त निर्माताओं के लिए पहली पीएलआई योजना की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में 120 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रोत्साहन निर्धारित किया गया था;
(ग) उक्त पीएलआई योजना को बंद करने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार को पता है कि देश में छोटे ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले 90 प्रतिशत फ्लाइट कंट्रोलर चीन से आयात किए जाते हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ड्रोन घटकों के स्वदेशीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय की ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दिनांक 30 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24) में कुल 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था। योजना की अवधि अब समाप्त हो गई है। इस योजना के तहत कुल 98.32 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि वितरित की गई।

(घ) और (ड.): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रमाणित और विशिष्ट पहचान संख्या के साथ पंजीकृत छोटे वर्ग के यूएएस मॉडल में स्थापित उड़ान नियंत्रकों के संबंध में भारत के मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज की तारीख तक 39 प्रतिशत उड़ान नियंत्रक चीन स्थित निर्माताओं से लिए गए हैं। मंत्रालय की पीएलआई योजना में ड्रोन घटकों का स्वदेशी निर्माण शामिल था।

******